Scheme of I.C.A.R. for More Income and Employment in Rural Areas

5543. SHRI HARINATH MISRA:

Will the Minister of AGRICUL-TURE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Indian Council of Agricultural search have recently drawn scheme to generate more income and employment opportunities for marginal farmers, landless labourers other economically weaker sections of the population in rural areas;
- (b) if so, the salient features there-
- (c) what concrete steps have been taken or are proposed to be taken to implement the scheme throughout the country; and
- (d) if no action has been taken the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION: MARI KAMLA KUMARI); (a) Yes, Sir.

- (b) An All-India Coordinated Project for generating additional income and employment in the market shed areas of Metropolitan cities is under preparation & processing in the ICAR.
- (c) While project proposals being processed in consultation with Ministry of Finance it was found that the Ministry of Rural Reconstruction. Government of India also have similar proposals under their consideration. Hence, to avoid duplication, it is proposed to explore possibilities of integrating these project proposals with those being formulated by the Ministry of Rural Reconstruction. However, the Ministry of Rural Reconstruction seem to have developed a proposal for setting up a Council for Advancement of Rural Technology (CART) which the Planning Commission have already cleared. Besides, the Planning Commission have also set up a Task Force for preparation

of All-India Coordinated Research Project for technologies for landless labour families. The report of the task force is awaited.

(d) The question does not arise.

जैसलमेर तथा बाइमेर में जनसंख्या के ग्रन्सार डाकघरों का खोला जाना

5544. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : नया संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि गांव में प्रति एक हजार की जनसंख्या पर डाकघर खोला जाता हैं ; श्रीर
- (ख) क्या राजस्थान के जैसलमेर ग्रौर बाइमेर के रेगिस्तानी ग्रौर पिछड़े जिलो में, जहां, कमश: 10 से 50 प्रतिशत किलो-मीटर जनसंख्या है श्रीर जहां गांव 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है ग्रीर कुछ गांवों में एक हजार की जनसंख्या है सरकार इन पिछड़े जिलों में विकास की गति तेज करने की दृष्टि से एक हजार की जनसंख्या के स्थान पर 500 की जनसंख्या पर डाकघर खोलने का मापदंड अपनाने के लिए तैयार हैं, ग्रीर यदि हां, तो उपर्युक्त निर्णय कव तक कियान्वित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एंव (ख). पहाडी, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों तथा प्रन्य ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघर विभागीय मानदंडों के अनुसार खोले जाते हैं, जिनका सारांश विवरण में दिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर ग्रीर बाडमेर दोनों जिले पिछडे क्षेत्रों की सूची में प्राते हैं। मौजूदा मानदंड के तीन श्राधार हैं तथा केवल जन-संख्या की छट के ब्राधार पर इन जिलों के किसी ग्राम को डाकघर खोले जाने के योग्य नहीं समझा जा सकता । फिलहाल इन मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।